राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16090/2017

वहीदुद्दीन पुत्र श्री रहीम बक्स, निवासी 9, चौकी रोड, राजसमंद----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग के माध्यम से, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, जयपुर.

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

4. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, उदयपुर----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री सुशील सोलंकी।
प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री सरवन कुमार।

माननीय जस्टिस श्री अरुण मोंगा

आदेश

08/02/2024

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ एक निर्देश की मांग करता है जिसमें उत्तरदाताओं को निलंबन की तारीख से सेवानिवृत्ति तक अपनी वार्षिक ग्रेड वृद्धि जारी करने और वृद्धि अनुदान पर याचिकाकर्ता की पेंशन को ब्याज के साथ वेतन बकाया के भुगतान सहित सभी संबद्ध लाभों के साथ संशोधित करने के लिए अनिवार्य किया जाए।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्यों को नीचे रेखांकित किया गया हैः याचिकाकर्ता ने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजसमंद में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य किया। एक जाँच के दौरान, कुछ अनियमितताएँ हुईं, जिसके कारण याचिकाकर्ता को 13.08.2004 के आदेश द्वारा विभागीय जाँच के लिए निलंबित कर दिया गया।

2.2 उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में त्रिलोक सिंह, वाहिदुद्दीन और श्रीमती मेहराज बानो के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) भी दर्ज की गई थी। इसके बाद, उन्हें 28.01.2012 (अनुलग्नक-1) के एक फैसले द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

2. 3 निलंबन के दौरान, याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, राजसमंद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अनुलग्नक-2 के अनुसार, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को अप्रमाणित पाया।

2. 4 प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के बावजूद, बाद में पूछताछ की गई, जिसके परिणामस्वरूप वही निष्कर्ष निकला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे। हालाँकि, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, और याचिकाकर्ता 31.05.2012 को सेवानिवृत्त हो गया, इस प्रकार अंततः निलंबन के तहत सेवानिवृत्त हो गया।

2. 5 21.09.2016 को याचिकाकर्ता पर दो साल के लिए पेंशन का 10 प्रतिशत रोकने का जुर्माना लगाया गया था। इस निर्णय के खिलाफ एक अपील को रखरखाव की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था, क्योंकि सजा के आदेश को राजस्थान के राज्यपाल की मंजूरी थी।

2. 6 अंत में, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद एक कार्यालय आदेश द्वारा ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि प्रदान की गई।

3. इसलिए तत्काल याचिका लगाई गई है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्क को सुना है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए हम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1951 (इसके बाद '1958 के नियम' के रूप में संदर्भित) के लागू नियम 16 (10ए) का उल्लेख करें, याचिकाकर्ता ने जिसके घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त नियम को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -"नियम 16 (10 ए)-अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यदि वह किसी आरोप के लेख पर पूछताछ प्राधिकरण के निष्कर्षों से असहमत है, तो ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा और ऐसे आरोपों पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज करेगा यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है और इसे जांच की रिपोर्ट की प्रति के साथ सरकारी कर्मचारी को उनके प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाएगा।"

6. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों को उनके वरिष्ठों के किसी भी अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप कर्मचारी को लाभ होना चाहिए।

7. इसके अलावा, सेवा कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत यह है कि जबकि दंडक प्राधिकरण एक जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों से असहमत होने का विवेकाधिकार रखता है, ऐसी असहमति एक स्वतंत्र मूल्यांकन से उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए दंडक प्राधिकरण द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश जारी करने की आवश्यकता होती

है, जिसमें नियम 16 (10 ए) द्वारा अनिवार्य रूप से कर्मचारी को जवाब देने का अवसर देने के बाद शुल्क-वार प्रतिक्रियाएं प्रदान की जाती हैं। हालाँकि, 1958 के नियमों के नियम 16 (10ए) के अनुसार, यहाँ ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई थी।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, 10.12.2013 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुनवाई के लिए 11.12.2013 निर्धारित की गई थी। मेरा विचार है कि यह सूचना 1958 के नियमों के नियम 16 (10ए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, क्योंकि असहमति का कोई कारण नहीं बताया गया था। रिट याचिका के पैराग्राफ 7 और 8 में विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य नोटिस नहीं दिया। यहां तक कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 10.12.2013 (अनुलग्नक-4) को नोटिस, जो उन्हें अगले दिन निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई के लिए रात भर का नोटिस प्रदान करता है, 11.12.2013, वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।

9. शत्रुतापूर्ण भेदभाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। यह पता चला है कि इसी तरह, सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के तहत मोहन लाल पालीवाल को भी एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक कार्यालय आदेश दिनांक 18.06.2008 द्वारा भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी के साथ उनके खिलाफ जांच को हटा दिया गया था। हालाँकि, आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के बरी होने के फैसले को देखते हुए, मोहन लाल पालीवाल को दी गई वही छूट याचिकाकर्ता को नहीं दी गई है।

10. याचिकाकर्ता 31.05.2012 को सेवानिवृत्त हुआ, और चूंकि उस समय की पूछताछ रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में थी, इसलिए पेंशन को रोक नहीं दिया जाना चाहिए था। 13.08.2004 से

सेवानिवृत्ति तक, निलंबन के दौरान याचिकाकर्ता को वार्षिक ग्रेड वृद्धि भी जारी नहीं की गई थी, जिसके लिए कोई प्रशंसनीय औचित्य नहीं है।

11. राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 29 का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जो अधिकृत प्राधिकारी द्वारा रोके जाने तक वेतन वृद्धि को अनिवार्य करता है। उक्त नियम 29 निश्चित रूप से वृद्धि का प्रावधान करता है जब तक कि रोक नहीं दी जाती। उक्त नियम इस प्रकार हैः - "नियम 29. निश्चित रूप से की जाने वाली वृद्धि जब तक नहीं रोकी जातीः "[नियम 26-ए, 27-ए और 30 के प्रावधानों के अधीन, एक वृद्धि सामान्य रूप से निश्चित रूप से तब तक की जाएगी जब तक कि इसे वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा नहीं रोका जाता है। वेतनवृद्धि रोकने के किसी भी आदेश में उस अवधि को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए इसे रोक दिया गया है और क्या भविष्य की वेतनवृद्धि को स्थगित किया जा रहा है। ((1) राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों और (2) गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों द्वारा वेतनवृद्धि लेने के संबंध में प्रक्रिया के लिए सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 155 का उल्लेख किया गया है।)"

12. ऊपर दिए गए नियम 29 के अनुसार, वेतनवृद्धि आमतौर पर निश्चित रूप से तब तक दी जाती है जब तक कि विशेष रूप से अधिकृत संस्था द्वारा रोक नहीं दी जाती है।

12. 1 वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता निलंबन के अधीन था। यह कानूनी सिद्धांत में अच्छी तरह से स्थापित है कि निलंबन स्वयं सजा का गठन नहीं करता है। हालाँकि, वेतनवृद्धि को रोकना 1951 के नियमों के नियम 14 के तहत एक दंडात्मक कार्रवाई मानी जाती है। इसलिए, वेतनवृद्धि को रोककर, याचिकाकर्ता को प्रभावी रूप से दंडित किया गया है, वह भी, आवश्यक विभागीय जांच किए बिना, इस तरह

की कार्रवाई को गैरकानूनी बनाते हुए। पहले का सजा आदेश दिनांक 21.09.2016 स्पष्ट रूप से ग्रेड वृद्धि को रोकने की सजा को निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता के लिए दोगुना खतरा हो सकता है, क्योंकि एक अलग दंडात्मक आदेश (दो साल के लिए उसकी 10 प्रतिशत पेंशन रोककर) के माध्यम से उसे पहले ही सजा दी जा चुकी थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दोनों नियमों यानी 1951 और 1958 को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तब से वेतनवृद्धि को रोकना 1958 के नियमों के नियम 14 के तहत एक स्वतंत्र सजा है और इस तरह के दंडात्मक उपाय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता निलंबन की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार है।

13. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 का नियम 89, याचिकाकर्ता को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का हकदार बनाता है यदि सेवानिवृत्ति लाभ देय होने के 60 दिनों से अधिक समय बाद अधिकृत किए जाते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुए, मेरा मानना है कि ब्याज की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान तक होनी चाहिए।

14. एक परिणाम के रूप में, याचिका को उचित परिणामों के साथ अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता के बकाया की गणना और संवितरण संबंधित सेवा नियमों के अनुसार किसी भी लागू ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।